कैशलेस भारत की राह में संभावित बाधाएँ

drishtiias.com/hindi/printpdf/potential-barriers-to-cashless-india

कैशलेस भारत की राह में संभावित बाधाएँ

207 भुगतान प्रति कार्ड हुआ स्वीडन में पिछले साल (कुल आबादी 98 लाख)

कैशलेस अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के शीर्ष-5 देशों बेल्जियम, फ्राँस, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन से तुलना करें तो भारत को अभी लंबा सफर तय करना है।

इंटरनेट की सुविधा नहीं

'डिजिटल अर्थव्यवस्था' के लिये इंटरनेट की उपलब्धता बेहद ज़रूरी है। शीर्ष देशों के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति इंटरनेट की उपलब्धता बहुत ही कम है। इंटरनेट तो छोड़िए भारत में मोबाइल भी 83 फीसदी लोगों के पास ही है।

शीर्ष देशों की तरह डिजिटल होने में कई अड़चनें

98 प्रतिशत नकदी का इस्तेमाल भारत में लेनदेन के लिये

2 फीसदी नकदी का ही इस्तेमाल होता है स्वीडन में

इंटरनेट की स्पीड भी अहम

- 5.5 सेकेंड औसतन समय लगता है भारत में पेज लोड होने पर
- 2.6 सेकेंड औसतन समय लगता है चीन में।

प्रति व्यक्ति इंटरनेट उपलब्धता के साथ-साथ उसकी स्पीड में सुधार होना भी ज़रूरी है। देश में अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ इंटरनेट की गति बहुत ही कम है। जबकि कैशलेस अपनाने वाले देश इस मामले में शीर्ष पर हैं।

देश	रैंक	रेटिंग (10 में से)
ब्रिटेन	5	8.57
स्वीडन	7	8.45
फ्राँस	16	8.11
बेल्जियम	22	7.83
कनाडा	25	7.62
भारत	138	2.69

(रिपोर्ट: आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स, 2016)

साक्षरता दर बढ़ाने की ज़रूरत

'कैशलेस भारत' के निर्माण के क्षेत्र में साक्षरता दर भी एक अहम कारण है। लोगों को साक्षर किये बिना उन्हें 'ई-पेमेंट', इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग से जोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा।

- 99 प्रतिशत साक्षरता दर स्वीडन, फ्राँस, बेल्जियम और ब्रिटेन में
- 74.4 प्रतिशत साक्षरता दर भारत में

साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता

डिजिटइजेशन की ओर बढ़ने में सबसे ज़्यादा चिंता साइबर चोरों से सुरक्षा की है। नोटबंदी से कुछ पहले ही देश में लाखों डेबिट कार्ड का डाटा चोरी हो गया था। कैशलैस अर्थव्यवस्था अपनाने वाले शीर्ष देशों के सामने भी यह चिंता बरकार है।

- भारत डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले में दूसरे स्थान पर (2014 की रिपोर्ट) है।
- 23 प्रतिशत डेबिट कार्ड पर खतरा।
- 1.40 लाख धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए स्वीडन में गत वर्ष।

अफ्रीकी देश भी हमसे आगे

हालाँकि कैशलेस अर्थव्यवस्था के मामले में केवल विकसित देश ही नहीं बल्कि अफ्रीका के देश भी हमसे आगे हैं। नाइज़ीरिया, ज़िम्बाब्वे और केन्या में बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है।